बाहर तैनात करने पर विचार नहीं किया गया। यह स्थानान्तरण नीति के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

कनिष्ठ इंजीनियरों (विद्युत) को जो 1996 के दौरान स्थानान्तरित होने अपेक्षित थे, पहले ही बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

General Pool Accommodation to Delhi Police Personnel

3630. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Head Constables, Assistant Sub-Inspectors, etc. of the Delhi Police are eligible for General Pool accommodation;

(b) if not, whether any personnel of Delhi Police are in occupation of the General Pool accommodation; and

(c) if so, what are the reasons for continuing allotment to such personnel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) No, Sir.

(b) and (c) Only gazetted staff of Delhi Police are eligible for accommodation from general pool as per Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963 as Delhi Police have their own pool of accommodation and Police colonies for non-gazetted staff.

बिहार में छोटे व मझौले शहरों के समन्वित विकास कार्यक्रम (आई०डी०एस०एम०टी०) का क्रियान्वयन

3631. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य":** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में छोटे व मझौले शहरों के समन्वित विकास (आई०डी०एस०एम०टी०) के अन्तर्गत कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रमों में किन-किन शहरों को शामिल किया गया है और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नालन्दा को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और नालन्दा को इस कार्यक्रम में शामिल किये जाने वाले प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) जी, हां।

(ख) अब तक आई०डी०एस०एम०टी० में शामिल बिहार के 40 शहरों की जिलावार सूची विवरण के रूप में संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) जी, नहीं।

(घ) आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम में शामिल करने के लिए प्राथमिकता वाले शहरों की पहचान और चयन राज्य सरकारों द्वारा स्कीम के दिशानिर्देशों के तहत किया जाता है बिहार सरकार ने नालंदा को निर्धारित प्राथमिकता वाले शहरों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण

आई०डी०एस०एम०टी० योजना में शामिल किए गए शहरों की सूची

(1979-80 के 31 मार्च, 1997 तक)

क्रम सं०	राज्य / शहर	जिला
बिहार		
1.	आरा	भोजपुर
2.	बेगूसराय	बेगुसराय
3.	बतिया	पश्चिम चम्पारयन
4.	चईवासा	सिंहभूम
5.	छपरा	सारन
6.	डालटनगंज	पालमु
7.	देवगंढ़	देवगढ़
8.	धनबाद	धनबाद
9.	दुमका	दुमका
10.	गिरडीह	गिरडीह
11.	गोपाल गंज	गोपालगंज
12.	हाजीपुर	वैशाली

क्रम सं०	राज्य / शहर	जिला
13.	हजारी बाग	हजारी बाग
14.	कटिहार	कटिहार
15.	सहरसा	सहरसा
16.	बिहारशरीफ	नालन्दा
17.	बोधगया	गया
18.	बकसर	भोजपुर
19.	दरभंगा	दरभंगा
20.	किशनगंज	किशनगंज
21.	मधुबनी	मधुबनी
22.	नवादा	नवादा
23.	पुरनिया	पुरनिया
24.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
25.	शिवान	शिवान
26.	जहानाबाद	जहानाबाद
27.	शाहीगंज	साहिब गंज
28.	बंका	भागलपुर
29.	गढ़वा	पालमु
30.	मुंगेर	मुंगेर
31.	भागलपुर	भागलपुर
32.	छत्रा	हजारीबाग
33.	गौंडा	गौंडा
34.	गुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
35.	राजगीर	नालन्दा
36.	फारबिसगंज	अररिया
37.	गया	गया
38.	लोहारडागा	लोहारडागा
39.	शिहोहर	सीतामढ़ी
40.	सुपोल	सहरसा

Unauthorised Construction/Alterations and Subletting of Government Quarters

3632. DR. B.B. DUTTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any investigations have been made by Government to check unauthorised construction/alterations and subletting of Government Quarters in Delhi;

(b) if so, the details thereof, locality-wise;

(c) the action taken/proposed to be taken against the persons found guilty; and

(d) the steps taken by Government to stop such activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (d) On receipt of a report of unauthorised construction/alterations, a show cause notice is issued to the concerned allottee for the removal of the said unauthorised construction/alterations within the stipulated period, and if the allottee fails to remove the unauthorised construction within the stipulated period, the allotment of accommodation is cancelled as per the provisions of the Allotment Rules and eviction proceedings initiated under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

As regards subletting of General Pool Residential Accommodation, 4488 cases of suspected subletting were detected as a result of door to door survey carried out in pursuance of Supreme Court directions and show cause notices were served on these allottees. Thereafter, upto September, 1996, 1085 General Pool Residential Accommodation has been cancelled and 634 got vacated/evicted.

Investment by HUDCO on Infrastructure Sector

3633. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) has